



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2003/भाद्र 11, 1925

No. 135]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2003/BHADRA 11, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 29 अगस्त, 2003

सं. टीएएमपी/53/2003-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और उक्त अधिनियम की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा सभी महापत्तन न्यासों के अपने-अपने दरमानों में, संलग्न आदेशानुसार, यह विनिर्दिष्ट करने के लिए कि उनमें निर्धारित दरें अधिकतम दरें हैं, समान रूप से एक सशर्तता समाविष्ट करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/53/2003-सामान्य

आदेश

(अगस्त, 2003 के 28वें दिन पारित)

भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन दिनांक 21 अगस्त, 2003 के पत्र सं. पीआर/11012/1/99-पीजी द्वारा इस प्राधिकरण को दरमान को अधिकतम दरों के रूप में निर्धारित करने और इसे अपने दरें निर्धारित करने संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित करने के लिए नीति निदेश जारी किया है ताकि महापत्तनों को अन्य पत्रों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कम दरों पर वसूली, यदि वे चाहें तो, करने का अधिकार हो। इसी प्रकार, इस प्राधिकरण द्वारा दरमान में निर्धारित छूट और कटौती निम्नतम स्तर के रूप में लागू होंगी और पत्तन न्यासों को उच्चतर छूट और कटौती करने का अधिकार होगा।

2. जैसा कि इस अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, इस प्राधिकरण के विचार प्राप्त करने के पश्चात् सरकार द्वारा यह निदेश जारी किया गया है। इस प्राधिकरण ने प्रस्तावित निदेश का पूर्णतः समर्थन किया क्योंकि इससे महापत्तन न्यासों को अपेक्षित अधिकार मिलता।

3. सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के लिए और इस निदेश के पीछे की मनशा को ध्यान में रखते हुए, यह प्राधिकरण यह निर्धारित करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों के सभी अनुमोदित दरमानों में सामान्य सशर्तता शामिल करना उचित समझा है कि इन दरमानों में शामिल दरें और छूट/कटौती क्रमशः अधिकतम और निम्नतम स्तर की हैं। यह व्यवस्था वर्तमान दरों के साथ-साथ भविष्य में निर्धारित की जाने वाली दरों पर भी लागू होगी।

4. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से, यह प्राधिकरण निम्नलिखित सामान्य सशर्तता को शामिल करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों के दरमान में संशोधन करता है :—

“दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम हैं : इसी प्रकार, कटौतियां और छूट निम्नतम हैं। पत्तन न्यास, यदि ऐसा चाहे तो, कम दरें वसूल कर सकता है और/अथवा उच्चतर कटौती और छूट दे सकता है।”

5. सभी महापत्तन न्यासों को एतद्वारा अपने दरमान में यह सशर्तता शामिल करने का निदेश दिया जाता है।
6. यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना के पश्चात् तत्काल प्रभावी होगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन III/IV/143/2003]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th August, 2003

No. TAMP/53/2003-Genl.— In compliance of a direction issued by the Government of India under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the said Act, the Tariff Authority for Major Ports hereby introduces commonly for all the major port trusts a general conditionality in their respective Scale of Rates to specify that the rates prescribed therein are ceiling rates, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/53/2003-Genl.

ORDER

(Passed on this 28th day of August, 2003)

The Government of India in the Ministry of Shipping (MOS) vide its communication No. PR/11012/1/99-PG dated 21 August, 2003 has issued a policy direction to this Authority under Section 111 of the MPT Act to fix the Scale of Rates as ceiling rates and to so specify in its notification fixing rates so that the major ports have the flexibility to charge at reduced rates, if they so desire, to compete with others. Similarly, the discounts and rebates prescribed by this Authority in the Scale of Rates will act as the floor level and the port trusts will have the flexibility of giving higher discounts and rebates.

2. This direction has been issued by the Government after obtaining the views of this Authority, as required under the relevant provisions of the Act. This Authority fully endorsed the proposed direction since it would give required flexibility to the major port trusts.

3. In order to implement the policy of the Government and bearing in mind the intention behind the direction, this Authority considers it appropriate to insert a general conditionality in all approved Scale of Rates of all major port trusts to prescribe that the rates and discounts/rebates contained therein are ceiling and floor levels respectively. This arrangement will apply to the existing rates as well as the rates to be fixed in future.

4. In the result, and for the reasons given above, this Authority amends the Scale of Rates of all the major port trusts to insert the following general conditionality therein :—

“The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The Port Trust may, if it so desires, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts.”

5. All the major port trusts are hereby directed to include this conditionality in their Scale of Rates.

6. This Order shall come into effect immediately after its notification in the Gazette of India.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[No. ADVT/III/TV/143/2003]